प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

14.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- मुख्यमंत्री ने कहा–सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों के मूल कैडर में अधिकार रखे जाएंगे। सुरक्षित।
- प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावी क्रियान्वयन से भ्रष्टचार पर लगा अंकुश।
- केन्द्र की कृषि ऋण योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को मिल रहा संबल।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिला के सरांहा के प्रवास पर।

शिक्षक–मूल कैडर

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हों। कल शिमला में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा सेवा शर्तों में भी राहत प्रदान करने और शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का एक अलग लोगो और वर्दी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 'नो मोबाइल फोन नीति' के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की, जो इस वर्ष एक मार्च से लागू होने जा रही है। उन्होंने विभाग को निर्धारित समय–सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए।

गोकुल बुटेल

प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को लेकर राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे हर स्तर पर पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने कल शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि तकनीक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए अलग–अलग पोर्टल और ऐप के जरिए विभागों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब 'हिम परिवार' पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों का डेटा एकत्र किया गया, जिसमें सामने आया कि 41 हजार से अधिक लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन दी जा रही थी, जिससे सरकार को हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि 'हिम केयर' योजना को भी डेटा और पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिल सके।

सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से सरकारी कामकाज में तेजी आई है और पारदर्शिता भी बढ़ी है।

नड्डा दौरा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आने का कार्यक्रम है। वे आज शाम बिलासपुर ज़िले में अपने पैतृक गांव विजयपुर पहुंचेगे। जे.पी. नड्डा 15 फरवरी को हमीरपुर के नेरी स्थित ठाकुर राम सिंह हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्ट्रीच्यूट में एक बैठक में भाग लेंगे।

पंचायत चुनाव

उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव इस वर्ष 31 मई से पहले करवाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें 30 अप्रैल से पहले पंचायतीराज चुनाव करवाने का आदेश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को एक महीने की राहत मिली है। अदालत ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव टाले नहीं जा सकते।

कृषि प्रोत्साहन–प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

किसानों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अनेक कृषि ऋण योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, पशुपालकों और मछुआरों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण योजना और केंद्रीय कृषि कामधेनु स्वर्ण ऋण योजना इन प्रमुख केन्द्रीय कृषि प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल हैं। इनके माध्यम से लाखों किसान परिवारों की बैंकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। विगत वित्त वर्ष के अंत तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से देश में 52 करोड़ युवाओं को लघु उद्यम शुरू करने हेतु 33 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं और इन पात्र युवाओं में 65 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता.....

मुख्यमंत्री दौरा

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सराहां में करोड़ों रुपये की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जिसके बाद वे कुश्ती ग्राउंड सराहां में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की इस दौरे से क्षेत्र वासियों को कई उम्मीदें हैं।

सेना भर्ती

अग्निवीर योजना के तहत सेना में विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, कलर्क, ट्रेडमैन और अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के पदों के लिए एक अप्रैल तक भारतीय सेना की आधिकारिक वैबसाईट पर ऑनलाईन पंजीकरण करवाया जा सकता है। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक ने बताया कि पंजीकरण के लिए ई–मेल आईडी और आधारकार्ड मोबाईल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है।

सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है–हिमाचल में 31 मई से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव करवाने का आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है– सुप्रीम कोर्ट का आदेश– 31 मई से पहले करवाएं स्थानीय निकाय चुनाव।

पंजाब केसरी लिखता है–आर.डी.जी. पर सर्वदलीय बैठक बीच में छोड़ बाहर आए भाजपा नेता। हिमाचल दस्तक के शब्द है–जनता को सीएम सुक्खू ने दिया भरोसा– निश्चित रहें,संकट से पार पा लेंगे शीघ्र आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है– हिमाचली हितों के लिए साम–दाम दंड, भेद सबका करेंगे इस्तेमाल।

दैनिक भास्कर की एक खबर है–अब वर्ल्ड हेरिटेज कालका–शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ेंगे स्वदेशी एयर ब्रेक सिस्टम से लैस कोच, यात्रा होगी सुगम।

''अंत में मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- मुख्यमंत्री ने कहा–सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों के मूल कैडर में अधिकार रखे जाएंगे। सुरक्षित।
- प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावी क्रियान्वयन से भ्रष्टचार पर लगा अंकुश।
- केन्द्र की कृषि ऋण योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को मिल रहा संबल।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिला के सरांहा के प्रवास पर।